लिये एक समिति गठित की गई हैं । उक्त समिति द्वारा पात्रता सूची तैयार किये जाने के बाद ही वास्तविक आवंटन किए जाएंगे ।

Meeting of Indian Rice Development Council

2558. SHRI MOHAN BABU: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether a meeting of the Indian Rice Development Council was held recently at - Hyderabad;

(b) if so, whether the Government of Andhra Pradesh had submitted a representation that small rice farmers do not benefit from the minimum support price for rice;

(c) the manner in which Government propose to assist small and marginal rice farmers who have very little marketable surplus;

(d) whether any scheme of financial assistance is being worked out for them; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTUkE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. The State Government of Andhra Pradesh had not submitted any representation to the Ministry of Agriculture, Government of India in this regard.

(c) The resource poor small and marginal farmers of Andhra Pradesh are provided assistance through outgoing Centrally Sponsored Integrated Cereals Development Programme in ricebased cropping systems areas (ICDP-Rice) and the Central Sector Rice Minikit Programme. Under the former, incentives are provided to the farmers on certified seeds, farm implements and sprinkler irrigation sets. Besides, field demonstrations and farmers trainings are also organised. Paddy seed of new high-yielding varieties are distributed under the latter scheme.

(d) and (e) There is no such proposal so far.

फलों और सब्जियों की ढुलाई में कठिनाइयां

2559. **श्री महेश्वर सिंह**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि देश में फलों और सब्जियों का वार्षिक उत्पादन लगभग 80 हजार मीट्रिक टन हो गया हैं और इन्हें मंडियों तक पहुंचाने में उत्पादकों और कृषकों को काफी कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि फल और सब्जियां शीघ्र खराब होने वाले पदार्थ होने के कारण इन्हें समय रहते मंडियों में पहुंचाना आवश्यक होता हैं;

(ग) क्या सरकार फल और सब्जियों की ढुलाई को एक आवश्यक सेवा घोषित करने पर विचार करेगी;और

(घ) यदि हां,तो कब तक और यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री अरविन्द नेताम**): (क) देश में फलों और सब्जियों का कुल उत्पादन एक लाख से अधिक हो गया हैं । तथापि उत्पादन के व्यवस्ततम मौसम को छोड़कर उत्पादन को मंडी तक लाने में कोई खास समस्या नहीं हैं ।

(ख) जी,हां ।

(ग) जी,नहीं ।

(घ) परिवहन संबंधी समस्याओं का समाधान काफी हद तक फसल कटाई के पश्चात देख रेख तथा विपणन संबंधी अवस्थापना का सृजन करके किया जा सकता हैं ताकि किसी खास समय में मंड्री में फलों तथा सब्जियों की भरमार को रोका जा सके तथा परिवहन प्रणाली पर पड़ने वाले अत्यधिक भार से बचा जा सके । इसके लिए,भारत सरकार ने,राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ किया हैं । जिसके तहत कटाई उपरान्त की देख-रेख जैसे पूर्व प्रशीतन एकक,शीत भण्डागार आदि के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए उदार तरीके से सहायता मुहैया कराई जाती हैं ताकि मंडी में की जाने वाली आपूर्ति को विनियंत्रित किया जा सके तथा उपभोक्ताओं को उत्पादन उपलब्ध हो सके ।

दूध की आपूर्ति

2560. **श्री रामजीलाल**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने देश में दूध की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को दूध की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारत से दूध के निर्यात को बन्द करने के लिए कोई आदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;यदि नहीं तो सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को दूध की नियमित आपूर्ति के लिये क्या योजना बनाई गई हैं ; और

(घ) इस समय देश में दूध का राज्य-वार उत्पादन कितना हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्वि करने के लिए विभिन्न उपायों के अलावा,सरकार ने दूध की आपूर्ति को बढ़ाने के उदेश्य से हाल ही में स्किम्ड दुग्ध चूर्ण तथा मक्खन और बटर ऑयल के आयात का उदारीकरण किया हैं।

(ख) और (ग) हालांकि आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं,तथापि निर्यात,लाइसेंस तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले मात्रात्मक परिसीमन के अध्याधीन हैं। गर्मी के महीनों के दौरान तरल दूध की उपलब्धता के दबाव को ध्यान में रखते हुए,सरकार ने 1995-96 के दौरान अभी तक कोई परिसीमन जारी नहीं किया हैं।

(घ) 1994-95 के दौरान प्रत्याशित दुग्ध उत्पादन को दर्शानेवाला राज्यवार ब्यौरा विवरण में संलग्र हैं।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान प्रत्याशित दुग्ध उत्पादन को दर्शानेवाला राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा

(हजार मी.टन)

क्रम.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	प्रत्याशित दुग्ध उत्पादन
1.	आन्ध्र प्रदेश	4100
2.	अरूणाचल प्रदेश	45
3.	असम	820
4.	बिहार	3215
5.	गोवा	30
6.	गुजरात	3800
7.	हरियाणा	3885
8.	हिमाचल प्रदेश	655
9.	जम्मू और कश्मीर	650
10.	कर्नाटक	3110
11.	केरल	2100
12.	मध्य प्रदेश	5060
13.	महाराष्ट्र	4450
14.	मणिपुर	115
15.	मेघालय	55
16.	मिजोरम	15
17.	नागालैण्ड	45
18.	उड़ीसा	590
19.	पंजाब	6400
20.	राजस्थान	4840
21.	सिक्किम	35
22.	तमिलनाडु	3965
23.	त्रिपुरा	40
24.	उत्तर प्रदेश	11400
25.	पश्चिम बंगाल	3095
	राज्यों का योग	631550
	संघ राज्य क्षेत्र	
26.	अडंमान एंव निकोबार द्वीप समूह	25
27.	चण्डीगढ़	40
28.	दादरा और नगर हवेली	4
29.	दमन और दीव	1
30.	दिल्ली	270
31.	लक्षद्वीप	1
32.	पाण्डिचेरी	29
	संघ राज्य क्षेत्रों का योग	370
	सकंल योग	63525

स्रोत: राज्य के पशुपालन एंव डेयरी विभाग।

Kendriya Vidyalayas Opened in the Country

2561. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of Kendriya Vidyalayas that have been opened during 1991—94 in (i) North Eastern Region (ii) in rest of India, year-wise;

(b) whether some Kendriya Vidayalayas have since been closed/are being closed; and

(c) if so, the details and reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF